© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
https://www.eurekajournals.com/shodh.html
ISSN: 2581-3501

सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

डॉ. अजय कृष्ण तिवारी[1]

[1]शिक्षाविद और अर्थशास्त्री और पीएच.डी. मार्गदर्शक।

सार

संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना 1945 में दुनिया के सभी देशों को शांति के लिए एक साथ काम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी ताकि दो विश्व युद्धों के अत्याचारों की पुनरावृत्ति न हो। जब इसे बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य राष्ट्रमंडल राष्ट्र के सदस्य थे, जिसमें उस समय की पांच-राष्ट्र शक्तियां शामिल थीं, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यूएसएसआर), ग्रेट ब्रिटेन, चीन संघ , और फ्रांस। उनके पास संगठन के भीतर एक विशेष स्थिति और वीटो का अधिकार है। दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के रूप में, इन पांच शक्तियों में से प्रत्येक के पास वीटो शक्ति और सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट है, जो संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है और इन निकायों में सबसे महत्वपूर्ण है।

कीवर्ड: संयुक्त राष्ट्र (UN), वीटो पावर, U.S.A, U.S.S.R, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस।

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के साठ साल बाद, एक महत्वपूर्ण सुधार हु आ है, दुनिया उन अभिनेताओं की बहु लताके साथ अधिक जटिल हो गई है जो इसे सफल बनाते हैं और जिन चुनौतियों का वे सामना करते हैं। 1960 के दशक में शुरू हु ईविऔपनिवेशीकरण की महान लहर और बाद में सोवियत संघ के पतन के कारण कई देशों को संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्यों में जोड़ा गया। इस प्रकार 2010 में सदस्य राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 192 हो गई, लगभग सभी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।

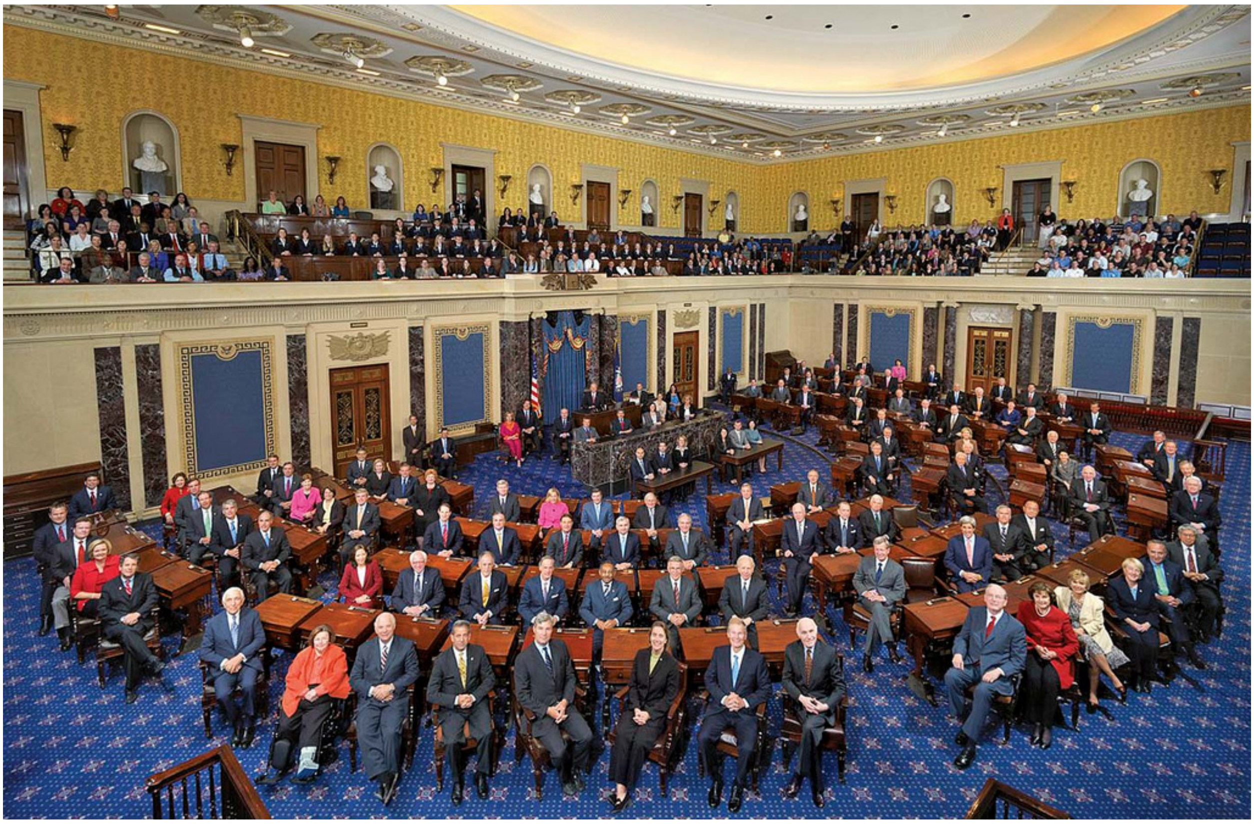

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

सुरक्षा परिषद का संस्थागत ढाँचा सिद्धांततः वही रहता है

इस विस्तार के बावजूद, सुरक्षा परिषद की संस्थागत संरचना सैद्धांतिक रूप से वही रही है। इस निकाय के सुधार पर वाद-विवाद इसके निर्माण के बाद से इसके साथ रहे हैं, लेकिन हाल के दशकों में बहु तकम सुधार किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा सुधार 1965 में हु आजब अस्थायी सदस्यों की संख्या छह से बढ़कर दस हो गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग में सुधार की आवश्यकता तेजी से जरूरी हो गई है, क्योंकि इसकी वर्तमान संरचना, विशेष रूप से स्थायी सदस्यों के रैंक में, समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता

जैसा कि हम देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद सुधार एक संवेदनशील मुद्दा है, जो प्रकृति में गहरा राजनीतिक और कूटनीतिक है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संबंध में, बहस हमेशा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से बढ़ी है, प्रत्येक परिषद में दूसरे के प्रवेश का विरोध करता है। जब प्रक्रियात्मक मुद्दे उठते हैं तो यह सुधार उत्तरोत्तर जटिल हो जाता है। वास्तव में, कुछ सुधारों को तदर्थ आधार पर लागू किया जा सकता है, जबकि अन्य, जैसे कि सुरक्षा परिषद और मतदान संरचना की संरचना में परिवर्तन के लिए चार्टर (3) में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार, यह संशोधन एक बार लागू हो जाएगा जब इसे महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अपनाया गया है और सुरक्षा के सभी स्थायी सदस्यों सहित उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। परिषद। (4)। इस प्रकार, कार्य और यहाँ तक कि दूर की जाने वाली चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, क्योंकि यद्यपि सुधार की आवश्यकता आम तौर पर सभी द्वारा स्वीकार की जाती है, इसके विवरण, सीमा और यहाँ तक कि समय पर असहमति बनी रहती है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

संयुक्त राष्ट्र इस उपाय को लागू करने में असमर्थ रहा है

महासभा ने सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर उनसे परामर्श करने के लिए सभी सदस्यों के लिए पहले से ही एक कार्य समूह का गठन किया है। 1993 और 2005 के बीच कई परामर्शों के बाद, इस कार्य समूह ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए (5)। वास्तव में, यह 2005 में संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व महासचिव की मदद से था कि कुछ प्रस्तावों को दिन के उजाले में देखा गया। कोफी अन्नान का प्रस्ताव अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 (6) करना था। हालाँकि, आज तक, संयुक्त राष्ट्र इस उपाय को लागू करने में असमर्थ रहा है, ऊपर उल्लिखित कठिनाइयों के कारण, विशेष रूप से पावर प्ले, स्थायी सदस्यों का वीटो, और इसे प्राप्त करने के लिए दो-तिहाई वोट इकट्ठा करने में कठिनाई। स्थायी सीटें बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं हु आहै। ठहराव की यह स्थिति सुरक्षा परिषद सुधार के पक्ष में अधिकारियों की अधीरता को बढ़ाती है। इस प्रकार, जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र, कम प्रतिनिधित्व महसूस कर रहे हैं, प्रत्येक निकाय के भीतर एक स्थायी सीट का दावा करते हैं जिसकी वैधता और विश्वसनीयता वे दावा करते हैं।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

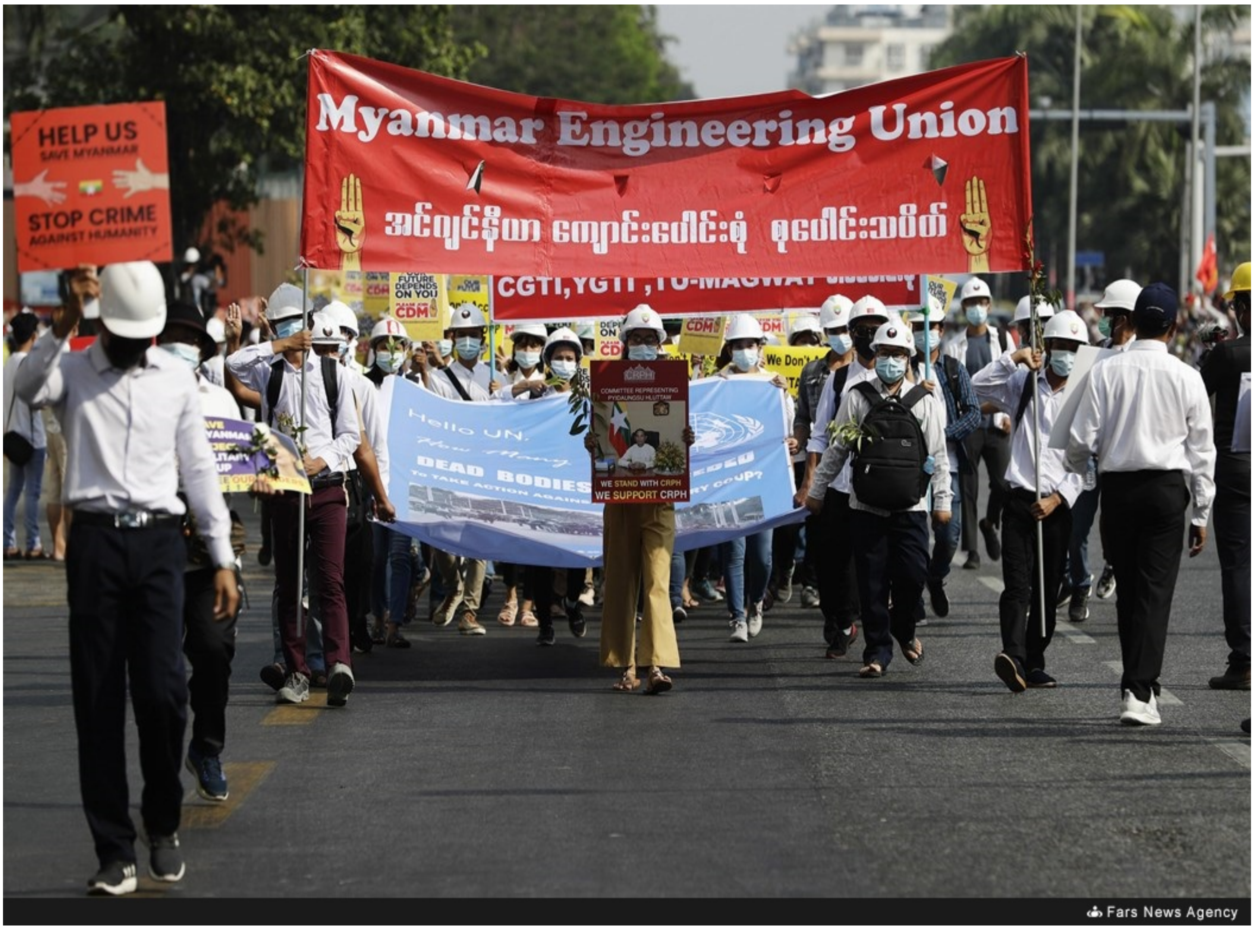

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के अंग के रूप में

ब्रिटेन और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थायी सदस्यों के रूप में भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। फ्रांस ने शक्तिशाली विश्व निकाय के भीतर दीर्घकालिक उपस्थिति का बोझ उठाने के लिए तैयार और सुसज्जित नई शक्तियों के उदय को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नथाली ब्रॉड हर्स्ट, फ्रांस के उप स्थायी प्रतिनिधिसंयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को कहा, "फ्रांस की स्थिति सुसंगत और प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि परिषद आज दुनिया का अधिक प्रतिनिधि हो, एक तरह से जो इसके अधिकार और प्रभावशीलता को और बढ़ाए।" "सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि, साथ ही सुरक्षा परिषद से संबंधित अन्य मामलों" पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा: "हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है नई शक्तियां।" सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक और सक्षम लोगों के उद्भव को ध्यान में रखना चाहिए।" एमएस ब्रॉड हर्स्ट ने कहा कि एक बड़ी परिषद में अपने कार्यकारी और परिचालन चरित्र को बनाए रखने के लिए 25 सदस्य तक हो सकते हैं। उसने कहा: " फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। हम स्थायी सदस्यों

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

सहित अफ्रीकी देशों में भी मजबूत उपस्थिति चाहते हैं। शेष सीटों को इस तरह से आवंटित किया जाना चाहिए कि समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

वीटो का सवाल "बेहद संवेदनशील"

उन्होंने यह भी कहा कि वीटो का सवाल "बेहद संवेदनशील" है और स्थायी सीट तय करने का अनुरोध करने वाले राज्यों पर निर्भर है। उसने कहा: "इस प्रतिबिंब में, उद्देश्य दो गुना रहना चाहिए: एक तरफ, सुरक्षा परिषद की वैधता को मजबूत करने के लिए, दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय शांति के रखरखाव में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए और सुरक्षा।" वह कहती हैं: "इस भावना में फ्रांस ने 2013 की शुरुआत में प्रस्ताव दिया था कि परिषद के पांच स्थायी सदस्य स्वेच्छा से और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वीटो के उपयोग को निलंबित कर दें। इस स्वैच्छिक दृष्टिकोण को चार्टर में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थायी सदस्यों से राजनीतिक प्रतिबद्धता।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

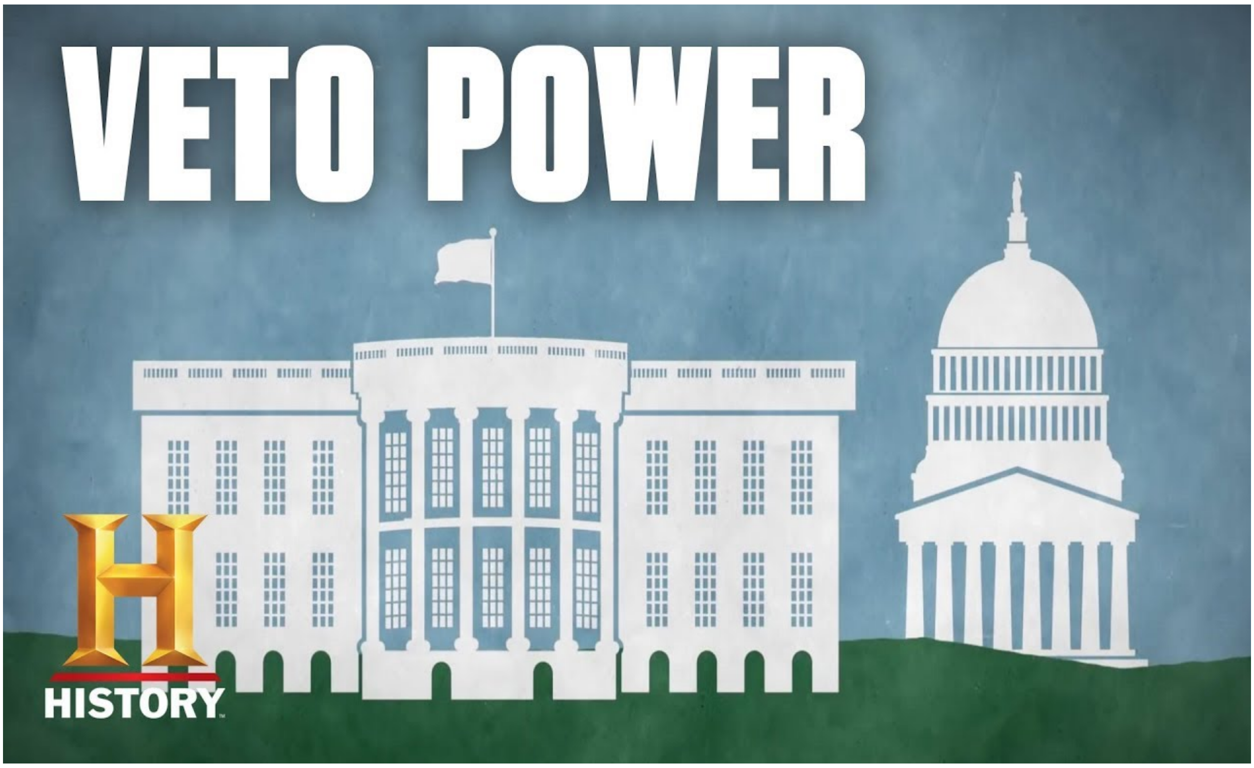

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

भारत यू.एन.एस.सी. का स्थाई सदस्य बनना चाहता है-

यदि 1945 में जब पांच शक्तियों ने बागडोर संभाली तो आज यह कार्य विश्व के चारों कोनों से आने वाली वर्तमान शक्तियों के अधीन होना चाहिए। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी, G4 में एकजुट होकर, 25 सदस्यों की एक परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें छह अतिरिक्त स्थायी सीटें शामिल हैं, प्रत्येक राष्ट्र पर समान शर्त लागू होती है। मौजूदा वैश्विक समस्याओं का मुकाबला करने के लिए, कई देशों ने नई स्थायी सीटों के निर्माण को रोकने के लिए एकजुट किया है, यह जानते हुए कि उनके सफल होने की संभावना नहीं है। यह पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना है जिसने "सर्वसम्मति के लिए एकजुट" (8) नकारात्मक समूह का गठन किया। अपने हिस्से के लिए, अफ्रीकी देशों ने 192 में से 51 मतों के साथ दो स्थायी सीटों का दावा किया जो दक्षिण अफ्रीका और मिस्र को सौंपी जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राय निर्णायक बनी हुई है, दो नए स्थायी सदस्यों के साथ 20 राज्यों से बनी एक परिषद को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन वीटो के अधिकार के बिना (9)। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों राष्ट्र दस या पंद्रह वर्षों के बाद 'बिग फाइव' के बंद घेरे को एकीकृत करने की संभावना के साथ 'अंतरिम' सुधार का प्रस्ताव रखते हैं (10)।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

सुरक्षा परिषद में इस तरह के सुधार से दुनिया का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होगा।

ब्रिटेन ने विस्तारित सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील का आह्वान किया था। इस अवसर पर बोलते हु ए गुरुवार को सुरक्षा परिषद सुधार पर महासभा की बहस के दौरान, राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा: "हमारा रुख सर्वविदित है। उन्होंने कहा: "हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के साथ-साथ भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों के निर्माण का समर्थन करते हैं। हम गैर-स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार करने का भी समर्थन करते हैं, जिससे सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लगभग 20 हो जाती है।" वुडवर्ड ने महसूस किया कि इस तरह के बदलाव परिषद को आज की दुनिया का अधिक प्रतिनिधि बना देंगे।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

भारत की ताकत इसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी रणनीतिक स्थिति है।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन सभी हुड़दंगियों का सामना करते हुए भारत अपनी क्षमताओं और अपने कुछ समकक्षों के समर्थन के बारे में जानते हुए इस "बंद घेरे" में प्रवेश करने के लिए बहुत आश्वस्त और दृढ़ महसूस करता है। वास्तव में, एक उभरते हुए देश के रूप में भारत की ताकत इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी जो चीन के करीब है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी सामरिक स्थिति में परिलक्षित होती है। और ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा: "एक अरब लोगों का देश, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ, दुनिया में अपनी जगह लेने के लिए तैयार है, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी जगह तब मिलनी चाहिए जब इसमें सुधार किया गया हो" (11)।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

कोविड-19 के समय में भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भेजकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मिसाल पेश की है।

भारत सरकार ने इस कोरोना महामारी के कई रूपों का बड़े ही संयम और धैर्य से मुकाबला किया है और इसमें हमें सफलता भी मिली है। इस दौरान हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वह इतना विशाल है कि कोरोना की दूसरी लहर में हमारे पास चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, आज हमारे पास अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं, जो इससे ज्यादा है.एन मांग। यह सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं ।हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। आज हमारे देशवासी गर्व से कहते हैं कि भारत का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षितहै जो बहु तआगे की सोचता है और उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रक्षा क्षेत्र में हो, रक्षा क्षेत्र में हो, हो यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र या कोई आंतरिक क्षेत्र है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रविवार को "आपातकालीन स्थितियों के लिए" COVID-19 के खिलाफ दो टीकों के उपयोग को अधिकृत किया, एक एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और दूसरा एक स्थानीय फर्म द्वारा।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले पुष्टि की थी कि वे भारत का पूरा समर्थन करेंगे

जुलाई 2010 में भारतीय विदेश मंत्री की मॉरीशस की यात्रा के दौरान, उनके मॉरीशस के विदेश मंत्री समकक्ष ने भारत की उम्मीदवारी के लिए अपने देश के समर्थन की पुष्टि की। "भारत पर्याप्त रूप से सुरक्षा परिषद में एक गैर-स्थायी सीट और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में बेहतर प्रतिनिधित्व का हकदार है," उन्होंने कहा (12)। बेनिग्नी राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए तो उनके समर्थन (13) को याद करने से नहीं चूके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले ही पुष्टि की थी कि वे चीन की बढ़ती ताकत के सामने एक मजबूत सहयोगी भारत का पूरा समर्थन करेंगे। नई दिल्ली में भारतीय संसद के समक्ष एक भाषण में, उन्होंने घोषणा की, "मैं आने वाले वर्षों में सुरक्षा परिषद में सुधार की आशा करता हूं जो भारत को एक स्थायी सदस्य बना देगा।"

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए एक नई प्रतिबद्धता के साथ शांति और सुरक्षा के लिए खतरों पर कार्रवाई करेगा

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति एक नई प्रतिबद्धता के साथ मिलकर, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का निर्णायक जवाब देने में सक्षम होगा। परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से चार, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र निकाय में स्थायी सीट देने के विचार का समर्थन किया है। अगले महीने, भारत द्वारा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद, गैर-स्थायी सदस्य के रूप में इसका वर्तमान दो साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारत और साथी G4 राष्ट्र ब्राजील, जर्मनी, जापान और नई दिल्ली ने तत्काल सुरक्षा परिषद सुधार के लिए आह्वान किया, क्योंकि वर्तमान समस्याओं से निपटने के तरीके पर शरीर कटु रूप से विभाजित है। भारत के अनुसार, यदि भारत जैसी उभरती शक्तियों के पास हॉर्सशू टेबल पर स्थायी सीट नहीं है, तो परिषद की वैधता खतरे में है क्योंकि यह वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है। G4 सुरक्षा परिषद में गहन सुधार की आवश्यकता को बनाए रखता है, विशेष रूप से स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों की श्रेणियों में सीटों की संख्या बढ़ाकर, समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके, अधिक खुली और समावेशी कार्य

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

प्रक्रियाओं को अपनाकर, और देशों के साथ संबंधों में सुधारों से भारत शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का निर्णायक जवाब देने में सक्षम होगा।

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

निष्कर्ष

दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत का समर्थन किया है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी की पूरी उम्मीद जगी है। हालांकि, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में न्यूजीलैंड के राजदूत ने कहा, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे कुछ देश सावधान हैं क्योंकि "वे अब से पंद्रह साल बाद यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के लिए अपनी सीटें खो सकते हैं"। यह स्थिति उतनी ही संभावित होगी जितनी यूरोपीय संघ सुरक्षा परिषद (15) पर केवल एक सीट का हकदार होगा। इसके अलावा प्रक्रिया जोखिम का प्रश्न प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेकिन भारत ने कोविड-19 के समय अधिकांश देशों को मुफ्त में Covaxinऔर Covishieldके टीके उपलब्ध कराकर मानवता के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। हल तुर्की और अफगानिस्तान को मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करके सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है।

संदर्भ

लेगाटो, अल्बर्ट, (1996) "पीसकीपिंग एंड यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म", इंटरनेशनल स्टडीज, वॉल्यूम। 27, नंबर 2, 1996, पृष्ठ 330.

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

संयुक्त राष्ट्र संगठन, (2010) "संयुक्त राष्ट्र का चार्टर", ऑनलाइन, http://www.unesco.org/education/info/nfsune... महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय स्लो टेक नोट ऑफ़ इमर्जेंस", ले मोंडे, 13 अक्टूबर 2010, पी. 5-7.

DESPIC-POPOVIC, हेलेन, (2010) "क्या सुरक्षा परिषद में सुधार संभव है? » इ्यूटी 16 अक्टूबर 2010, पृ. 21-23.

लुक्स इंडिया मस्ट हेव इट्स प्लेस ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्ग लंदन एंड दिल्ली एएफपी, 21 जनवरी, 2008, http://afp.google.com/article/ALeqM5live2cjZWoy9H। (पृ. पर परामर्श किया गया) 30 अक्तूबर, 2010).

"मॉरीशस सुरक्षा परिषद में एक सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा", 7 अप्रैल, 2010, https://www.lexpress.mu/story/13532-maurice-soutie... (30 अक्टूबर 2010 को पुनः प्राप्त) पेज गया).

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए बेनिन का समर्थन", 20 मार्च, 2009, http://www.lanouvelletribune.info/index.php?o... (30 मार्च, 2009 को पुनःप्राप्त) पृष्ठ) । अक्टूबर 2010).

"बराक ओबामा यूएन में एक स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करते हैं", एक्सप्रेस, 8 नवंबर 2010, ऑनलाइन, http://www.lexpress.fr/actualites/2/barrack-Obama-s। .. (8 नवंबर, 2010 को पुनः प्राप्त पृष्ठ).

जेनेट, अलीज़ंद्रा, अस्पष्टता। अंतिम संशोधित: 2010-11-29 14:12:46.

एन.डी.एल.आर.: यह संभव है कि इस लेख के शोध और लेखन के समय सक्रिय हाइपरलिंक बाद में सक्रिय न हों। बुद्ध का फैसला: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को वैध बनाने की मंजूरी सितंबर 2022 को दी।

भारत: मोटर वाहन उद्योग के धुंध और विस्तार के बीच दुविधा, मार्च 2022, पीपी-24-31.

भारत और रूस: (2022) सहयोगी या सामरिक सहयोगी? जनवरी 2022, पीपी-21-24.